बिजली दरें तय करने की मियाद पूरी ,नियामक आयोग की सुस्ती से गतिरोध

टैरिफ आदेश में देरी से फंसे जनहित से जुड़े कई फैसले

120 दिनों में दरें जारी करनी होती हैं प्रस्ताव के बाद

05 जून को मियाद पूरी हो चुकी है बिजली दरें तय करने की

सूरते हाल

■ रोहित मिश्र

■ स्मार्ट मीटरों के दाम जनता से न लिए जाने के मामले पर भी आदेश आना है

■ बहुमंजिला इमारतों के अलावा घरों में छोटी दुकान करने वालों पर भी देनी है व्यवस्था

लखनऊ। बिजली की दरें तय करने की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन नियामक आयोग ने अब तक टैरिफ आदेश जारी नहीं किए हैं। ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ है। इस टैरिफ आदेश के साथ ही स्मार्ट मीटरों के दाम जनता से लेने या न लेने, बहुमंजिला इमारतों के उपभोक्ताओं की तमाम शिकायतों और घरों में छोटी दुकान करने वाले उपभोक्ताओं के मसलों पर भी नियामक आयोग को व्यवस्था देनी है। हालांकि, टैरिफ आदेश में देरी से जनहित के ये मसले भी अटक गए हैं।

कानून के मुताबिक बिजली कंपनियों द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव स्वीकार करने के 120 दिनों में बिजली की दरें जारी करनी होती हैं। इस लिहाज से यह मियाद 5 जून को पूरी हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक बिजली की दरें जारी नहीं हुई हैं। आयोग को न केवल बिजली की दरें जारी करनी हैं बल्कि जनसुनवाई और राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उठे मुद्दों पर भी व्यवस्था देनी हैं। इनमें स्मार्ट मीटरों के दाम जनता से लिए जाने का भी मसला शामिल है। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग से मांग की है कि पुराने मीटरों को बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर आने वाला खर्च जनता से उनकी बिजली दरों में वसूला जाए। इस पर तमाम आपत्तियां हैं। नियामक आयोग इस पर क्या व्यवस्था देता है, उसका असर न केवल इस साल की बिजली दरों पर पड़ेगा बल्कि आने वाले वर्षों में भी जनता की बिजली दरों पर इसका असर रहेगा।

इमारतों में बिजली की खपत पारदर्शी बनाना चुनौती

बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को साझा क्षेत्र में इस्तेमाल बिजली की खपत की जानकारी नहीं होती है। यह मसला कई साल से नियामक आयोग के पास हर सुनवाई में पहुंच रहा है। बीते साल का टैरिफ आदेश जारी करते हुए नियामक आयोग ने इस मसले पर अलग से आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके वह आदेश नहीं आए। उम्मीद है कि इस साल आदेश में खपत की पारदर्शी व्यवस्था संबंधी आदेश होंगे। ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में तकरीबन 35 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपने घरों में छोटी दुकान करते हैं। इन उपभोक्ताओं को अलग से वाणिज्यिक कनेक्शन लेने से छूट देने की मांग हो रही है। यह मसला भी टैरिफ आदेश के साथ ही सुलझेगा।

बिजली दरों में कमी पर भी देना है फैसला

बिजली दरों की सुनवाई के साथ ही बिजली दरों में कमी की मांग की गई थी। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा था कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की बकाया रकम देखते हुए या तो एकमुश्त कमी की जाए या अगले पांच साल तक बिजली दरों में रियायत दी जाए। ऐसे में इसपर क्या फैसला आएगा यह देखने वाली बात होगी।

उपभोक्ता परिषद ने आपत्ति दाखिल की थी

उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव पर यह कहते हुए आपत्ति दाखिल की थी कि केंद्र की योजना आरडीएसएस के तहत मीटरों के दाम जनता से नहीं वसूले जाने हैं। इसके अलावा अगर इनके दाम बिजली दरों में जोड़े जाते हैं तो कई से दोहरी वसूली होगी और कई ऐसे भी उपभोक्ता होंगे, जिनके यहां मीटर न लगने के पहले ही उन्हें भुगतान करना होगा। साथ ही यह वसूली अंतहीन भी रहने की संभावना बन जाएगी।

शिलापट पर नामों की प्रमाणित फोटो के बाद ही दूसरी किस्त

निर्देश

■ शासन ने शिलापट पर नामों का विवाद दूर करने को लेकर दिया निर्देश

■ जनप्रतिनिधियों के नामों को तय फांट साइज में लिखाना होगा अनिवार्य

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने विकास कार्य स्थलों पर शिलापट पर जनप्रतिनिधियों का नाम लिखाए जाने को लेकर होने वाले विवाद को दूर करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके लिए विकास कार्य स्थल पर जनप्रतिनिधियों के नामों के लगने वाले शिलापट की अब प्रमाणित कापी देने के बाद ही विकास कार्य की दूसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि में अगली किस्त प्राप्त करने के लिए अब उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जनप्रतिनिधियों के नाम युक्त शिलापट, पट्टिका की फोटो डीएम, नगर आयुक्त वर्ग ए को से प्रमाणित कराते हुए देनी होगी। इसके सत्यापन के बाद ही अब निकायों को विकास कार्य की दूसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा।

शासनादेश में कहा गया है कि शिलापट को लेकर पूर्व में भी कई निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नगर विकास की विभिन्न योजनाओं, वित्त आयोगों की धनराशि से कराए जाने वाले कामों से संबंधित शिलापट्टों पर तय व्यवस्था के अनुसार नाम लिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, महापौर, विधायक, नामित नोडल सदस्य, पालिका व पंचायत अध्यक्ष का नाम प्रोटोकॉल के अनुसार अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाएगा।

नामों के लिए फांट साइज भी तय

इन नामों के लिए फांट साइज भी अलग-अलग तय किए गए हैं। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं व वित्त आयोगों से प्राप्त धनराशि से काम के शिलान्यास व लोकार्पण के दौरान जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकाल के अनुसार आमंत्रित करने की व्यवस्था है। इसलिए इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों को किसी तरह की कोई शिकायत न हो। शासनादेश में कहा गया है कि शासन के निर्देशों का पालन कुछ निकायों द्वारा सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी शासन को मिल रही है।

सियासत 30s

लखनऊ में रविवार को नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया।

नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन

लखनऊ। नीट पेपर लीक और साथियों की गिरफ्तारी समेत अन्य मसलों का विरोध करने के लिए रविवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) कार्यकर्ता रविवार को सड़क पर उतरे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और यूपी एनएसयूआई के मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान, राष्ट्रीय सचिव प्रणव पाण्डेय की अगुआई में जनभवन (पूर्व में राजभवन) घेरने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने माल एवेन्यू में ही रोक लिया।

महिला-किसान सशक्तीकरण को 4.95 करोड़

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) में 4.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में यह राशि खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने 2 करोड़ 97 लाख 50 हजार और राज्य ने 1 करोड़ 98 लाख 33 हजार रुपये दिए हैं।

नामित पार्षदों को दिया जाए यथोचित स्थान

लखनऊ। राज्य सरकार ने निर्वाचित पार्षदों की तरह नामित पार्षदों को भी यथोचित स्थान देने का निर्देश निकायों को दिया है। विशेष सचिव नगर विकास सत्य प्रकाश पटेल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों और निकायों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर सदस्य नामित करने की व्यवस्था है। उन्हें नियमानुसार शपथ ग्रहण कराए जाने के साथ ही यथोचित स्थान दिया जाएगा।

छांटे गए कर्मचारियों की बहाली हो: संघर्ष समिति

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने छांटे गए संविदा कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। संघर्ष समिति ने कहा है कि जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा तक यह मान चुके हैं कि संविदा कर्मचारियों की छंटनी गलत हुई है तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें हस्तक्षेप करें। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बीते डेढ़ साल में 25 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की छंटनी की गई। इन कर्मचारियों को विद्युत प्रणाली के संचालन और रखरखाव का वर्षों से अनुभव था।

'दस फीसद अतिरिक्त वसूली पर रुख स्पष्ट करें'

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के पहले राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि नियामक आयोग स्पष्ट कर चुका है कि पावर कॉरपोरेशन का आदेश नियामकीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उपभोक्ताओं से वसूली जारी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस मसले पर नियामक आयोग सख्त रुख अपनाते हुए पावर कॉरपोरेशन से बार-बार आंकड़े, गणना की विधि और अन्य अभिलेख मांग रहा है।

पेड़ों को यूनिक आईडी संग संपत्ति का दर्जा भी मिलेगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए समाज कल्याण विभाग ने नई शुरुआत की है। विभाग सभी सर्वोदय विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों में वृक्ष संपत्ति प्रबंधन योजना लागू की है। इसके तहत प्रत्येक पेड़ की एक यूनिक आईडी होगी। इससे निगरानी, संरक्षण और प्रबंधन बेहतर होगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

हर पेड़ का तैयार होगा डिजिटल डाटा बैंक: नई व्यवस्था के तहत पेड़ों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक पेड़ को एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी और उसकी प्रजाति, स्थान, अनुमानित आयु तथा वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण वृक्ष परिसंपत्ति पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

लखनऊ, कानपुर आगरा में अतिरिक्त पार्किंग स्थल बनेंगे

लखनऊ। उच्चस्तर पर हुई बैठक में बताया गया है कि लखनऊ में 17, कानपुर में 24 और आगरा में 19 अतिरिक्त पार्किंग स्थलों को चिह्नित किया गया है। संबंधित शहरों के नगर निगम और विकास प्राधिकरणों द्वारा पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए इनके द्वारा भूमि को चिह्नित किया जाएगा और जरूरत के आधार पर इसका निर्माण कराया जाएगा। उच्च स्तर पर हुई बैठक के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा इस संबंध में लखनऊ, कानपुर और आगरा के मंडलायुक्तों के साथ आवास, नगर विकास, पर्यटन और परिवहन विभाग को निर्देश भेजा गया है।

पीएसी में बैंड के लिए होगी 1254 जवानों की भर्ती

जॉब्स

■ पुलिस स्टेट बैंड की नियमावली भी हो रही तैयार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएसी बैंड को विस्तार दिए जाने की योजना है। पीएसी में बैंड के लिए कुल 1254 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें पहले चरण में 704 पदों के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है।

नए पदों के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बैंड नियमावली बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पहले चरण के बाद शेष पदों के गठन का प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय के जरिए शासन को भेजा जाएगा। पीएसी में अभी 33 वाहिनियों में 32 ब्रास बैंड और एक पाइप बैंड है। बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष पीएसी बैंड को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और नए पदों पर भर्ती से जुड़ा प्रस्तुतिकरण दिया गया था। पीएसी बैंड को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 32वीं वाहिनी पीएसी के पाइप बैंड को एसएसबी लखनऊ में चार सप्ताह का खास प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अन्य वाहिनियों के बैंड कर्मियों को सीआरपीएफ अकादमी, गुरुग्राम में प्रशिक्षण कराने का प्रस्ताव है।

अगले चुनाव में हार के डर से घबरा गई है सपा: अनिल

लखनऊ। प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और प्रवक्ता अनिल दुबे ने सपा पर तीखा हमला बोला है।

जारी बयान में कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मौजूदा सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में स्कूलों की क्या स्थिति थी?

छोटे कट की सर्जरी से पित्ताशय निकालने का उपचार

कम दर्द व कम अवधि में डिस्चार्ज

अनुभवी सर्जनों की टीम द्वारा आधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपचार

77+ इंश्योरेंस पार्टनर व CGHS, ECHS सहित

प्रभावी व आधुनिक सर्जिकल उपचार के लिए वर्षों से भरोसेमंद केंद्र

Dr. Girish Pandey
MS (General Surgery)

Dr. Amit K. Tiwari
MS (General Surgery)

24x7 EMERGENCY SERVICES
0542-7181911/ 945
For booking
Lanka, Varanasi
www.heritagehospitals.com

बेटी किसी की भी हो, सम्मान सबका होना चाहिए: अटावले

■ प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लखनऊ में नवंबर में जनसभा करेंगे

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बेटी किसी की भी हो, सम्मान सबका होना चाहिए। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। प्रदेश में अपनी पार्टी को और मजबूत करना है। नवंबर में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं।

यह बात रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (अटावले) के प्रमुख व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अटावले ने कही। वह लखनऊ स्थित वीवी आईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश सिंह की बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी को निंदनीय बताया। कहा कि सभी की बेटी सम्मानीय होती है। कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ नहीं हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हैं। बताया कि लखनऊ में नवंबर में पार्टी की जनसभा है।

एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश में विस चुनाव समय से पहले नवंबर-दिसंबर में होंगे। यदि होते हैं तो जनसभा उससे पहले कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म ट्रस्ट में गैर धर्म के लोग नहीं होने चाहिए। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और सिख ट्रस्ट में गैर धर्म के लोग नहीं हैं। फिर बुद्धिज्म ट्रस्ट में ही ऐसा क्यों।

मोदी के नेतृत्व में निवेश बढ़ा फिर सरकार बनेगी: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हुआ है। यही कारण है कि आज यहां विदेशी निवेश बढ़ा है।

अमेरिका हमारे देश में 27 लाख करोड़ निवेश करने वाला है, जिससे काफ़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। कहा कि ईरान - अमेरिका युद्ध खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की भी यही इच्छा है। हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। वर्ष 2027 में प्रदेश में योगी और वर्ष 2029 में केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।

भाजपा नकारात्मक राजनीति पर करोड़ों खर्च करती है: सपा

अखिलेश बोले, पीडीए का अर्थ प्रेम, दया और अपनापन

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को विजन इंडिया संवाद के बाद मीडिया से बातचीत में पीडीए का अर्थ प्रेम, दया और अपनापन बताया।

सपा मुखिया ने नौट, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। कहा कि भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है और इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। प्रधानमंत्री ने यदि इजरायल के बाद अपना विमान ईरान में उतार दिया होता तो न युद्ध होता और न ही पेट्रोल-डीजल महंगे होते। सपा मुखिया ने कहा कि अब यूपी के विकास का रास्ता समाजवादी निकालेंगे। ठेला हटाओ, सामान उठाओ, हफ्ता दो, लोन के लिए चक्कर काटो, बारिश आई कमाई बंद, बिजली कई कारोबार बंद जैसी स्थिति खत्म होनी चाहिए।

अब उजाड़ना बंद होगा और बसाना शुरू होगा। वेंडर्स सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करेंगे। मानसून सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजेंगे और कम खर्चे पर पर मौसम बीमा कराएंगे।

भविष्य में सपा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी: केशव

परिवारवाद व माफियावाद को जनता नकारेगी :डिप्टी सीएम

मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि भविष्य में सपा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी और उसका हश्र पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से भी बुरा होगा।

उन्होंने कहा कि जनता परिवारवाद, गुंडे-माफियाओं और दंगाइयों की राजनीति को स्वीकार करने वाली नहीं है। भाजपा 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी और मुरादाबाद की सभी छह विधानसभा सीटों समेत प्रदेश में 325 सीटें जीतेगी। रविवार को सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेसवार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और प्रदेश इसमें बराबर का भागीदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार 2047 तक बनी रहेगी।

आज से पूर्व बुकिंग पर मिलेगी खाद

लखनऊ। रामपुर एवं सीतापुर में 15 जून से यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों का वितरण 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल' ऐप के माध्यम से पूर्व बुकिंग के आधार पर किया जाएगा। किसानों को उर्वरक के लिए ऐप पर बुकिंग करनी होगी, जिसके बाद वे निर्धारित विक्रेता से अपनी खाद प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से किसानों को समय पर और सुनिश्चित उर्वरक की उपलब्धता होगी, निकटतम विक्रेता की खोज आसान होगी और उनके समय व श्रम की भी बचत होगी।

बसपा बढ़ा रही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां

■ भाईचारा कमेटी की बैठकों संग सेक्टर-बूथ स्तरीय समीक्षा पर जोर

■ अयोध्या-अकबरपुर में सभाओं से पदाधिकारियों में बढ़ाएंगे उत्साह

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरने के लक्ष्य को साधने के लिए कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करती नजर आ रही है। यूपी के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर चुनावी तैयारी तेज की गई है।

पार्टी दलित-ओबीसी कमेटी की बैठकों के जरिए जिलों में अपने कोर वोट को साधे रखने के प्रयास में है। साथ ही 22 व 23 जून को अयोध्या व अंबेडकरनगर में दो बड़ी जनसभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में जोश भरने की तैयारी है। खोई ताकत जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जिला लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो इन दिनों कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। वहीं पार्टी ने दलित-ओबीसी वर्ग के बीच पकड़ बनाए रखने के लिए भाईचारा कमेटी की बैठकों में जिला संयोजकों को जमीनी स्तर पर वोट बैंक की वास्तविक स्थिति के आंकलन का टास्क सौंपा गया है। इसकी रिपोर्ट पार्टी सुप्रीमो तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही सेक्टर व बूथ स्तरीय समीक्षा बैठकों में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और मिशन-2027 की तैयारियों को कार्यकर्ताओं के बीच धार देने का निर्देश है। पार्टी ने इस माह प्रस्तावित दोनों जनसभाओं को सफल बनाने का जिम्मा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपा है। पार्टी बड़ों से लेकर बूथ स्तर तक पूरी सक्रियता लाना चाह रही है।

उपलब्धि | गाजियाबाद में 3511 व नोएडा में 1737 करोड़, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद के निर्यात में मामूली बढ़त

निर्यात में पांच जिलों की बादशाहत कायम

■ विनोद पाण्डेय

लखनऊ। स्मार्ट फोन, आभूषण, सूती और सिंथेटिक कपड़े और हड्डीरहित मीट की बदौलत गौतमबुद्ध नगर प्रदेश के निर्यातक जिलों की टॉप टेन सूची में हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ऊपर है। यही स्थिति बनी रही तो चालू वित्तीय वर्ष में गौतमबुद्ध नगर का निर्यात एक लाख करोड़ को पार कर जाएगा। सामूहिक प्रदर्शन की बात करें तो गाजियाबाद का निर्यात सबसे बेहतर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में गाजियाबाद ने 3511 करोड़ और गौमतबुद्ध नगर ने 1737 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की है। कानपुर नगर, उन्नाव तथा मुरादाबाद बाद भी मामूली बढ़त के साथ टॉप टेन की सूची में अपने स्थान पर बरकरार हैं। गाजियाबाद आयरन एंड स्टील, मेटल, दवाइयां, फार्मा कंपोनेंट का बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। यहां हड्डीरहित मीट का बड़ा कारोबार है। इन उत्पादों को निर्यात में गाजियाबाद ने रिकार्ड बढ़त दर्ज की है। कानपुर नगर अपने परंपरागत उत्पादों लेदर, फुटवियर, आयरन, स्टील तथा कच्चा चमड़ा के निर्यात के साथ टॉप फाइव में अपनी जगह बनाए हुए है। 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में 245 करोड़ का अधिक निर्यात किया है। अमरोहा से आर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक उत्पाद, फर्नीचर, स्टील तथा सुगंधित ऑयल तथा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है।

01 लाख करोड़ को पार कर जाएगा नोएडा का निर्यात इस वित्तीय वर्ष में

■ गाजियाबाद का निर्यात सबसे बेहतर रहा सामूहिक प्रदर्शन में

प्रदेश के निर्यातक जिलों की टॉप टेन सूची

जिला	2024-25	2025-26
नोएडा	95,966	97,703
गाजियाबाद	15,217	18,728
कानपुर नगर	10,587	10,823
मुरादाबाद	10,578	10,639
आगरा	7691	8,907
अलीगढ़	7348	8,253
भदोही	5189	6,162
उन्नाव	5030	5,569
अमरोहा	2867	2,825
संभल	2449	3,521

लखनऊ को लेकर संभावना

पिछले वर्ष टॉप-15 की सूची में लखनऊ भी जगह बनाई थी। करीब 1771 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ 13वें स्थान पर था। यहां से न्यूक्लियर रिऐक्टर, मशीनहीं, आयरन एंड स्टील तथा चिकनकारी के कपड़े निर्यात किए जाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर विकसित हो जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में यहां से निर्यात और बढ़ने की संभावना है। निर्यातकों का कहना है कि औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होने के निर्यात पर असर पड़ेगा।

यूको बैंक

आंचलिक कार्यालय : धनश्री कॉम्पलैक्स, प्रथम तल, डी-63/8-1एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी

नियम 8(6) अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण वित्तीय आस्ति का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम -2002 के सपठित नियम 8 (6) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास सान्पिक बंधक रखी गई है। यह सूचना आम जनता को एवं विशेष रूप से ऋणकर्ता/ जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति को, यूको बैंक (प्रतिभूतिदाता) के पास बंधक है एवं जिसका प्रतीकात्मक कब्जा यूको बैंक (प्रतिभूतिदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। निम्नलिखित सम्पत्ति को '' जो है, जैसा है, जहा है'' के आधार पर 18.07.2026 को यथास्थिति ई निलामी (Baanknet Portal) द्वारा बिक्री की जायेगी।

ई - नीलामी की तारीख व समय- 18.07.2026, प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक

क्र. स.	शाखा का नाम ऋणी व जमानतकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जा तिथि/कब्जा की वास्तु स्थिति (वास्तविक / प्रतीकात्मक)	मॉग सूचना की तिथि व बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / अग्रिम मूल्य / निविदा बढ़ोतरी राशि	प्राधिकृत अधिकारी का विवरण
1.	वाराणसी मुख्य शाखा ऋणी : मेसर्स राज ट्रेडर्स प्रापराईटर : श्रीमती राज रानी महरोत्रा पत्नी श्री गोपी नाथ महरोत्रा, पता : भवानी शंकर काम्पलेक्स, बांसफाटक, वाराणसी, पिन - 221001 जमानतदार : 1. श्रीमती राज रानी महरोत्रा पत्नी श्री गोपी नाथ महरोत्रा, 2. श्री गोपी नाथ महरोत्रा, 3. श्री आदित्य महरोत्रा, 4 सुश्रि छवि महरोत्रा पता: सभी निवासी बी 15/31ए संजय अपाटमेन्ट, काटन मिल, चौकाघाट, वाराणसी पिन - 221002	सम्पत्ति के समस्त जिसमें एक फ्लैट जिसका अनुपातिक जमीन का हिस्सा 19.05 वर्ग मीटर और सम्पूर्ण बिल्ट-अप क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर जो कि श्रीमती राजरानी मेहरोत्रा पत्नी श्री गोपी नाथ मेहरोत्रा के नाम पर हैं। जो कि उप निबन्धक प्रथम वाराणसी के यहाँ बही सं0-1, जिल्द सं0 2072, पृष्ठ सं0- 123 से 148 क्रमांक सं0 - 236 दिनांक 20.01.2009 को पंजीकृत है स्थित फ्लैट नं0 31, ब्लाक नं0 बी -13, मकान नं0 जे -13/93-88-15/31, संजय अपार्टमेन्ट, घुरना काटन मिल, चौकाघाट, वार्ड/ परगना - जैतपुरा, तहसील और जिला वाराणसी, उत्तरप्रदेश। चौहद्दी - पूरब- फ्लैट नं0 31, ब्लाक बी -14, पश्चिम- भूतल पर खुली जमीन उसके बाद ब्लाक नं0 30, उत्तर - भूतल पर खुली जमीन उसके बाद फ्लैट नं0 31, ब्लाक बी -13, दक्षिण- भूतल से आसमान तक खुली जमीन उसके बाद फ्लैट नं0 31, ब्लाक बी -17	18.11.2025 (प्रतीकात्मक)	18.08.2025 रू 17,69,412.02 दिनांक 17.08.2025 तक (जिसमे ब्याज 31.08.2024 तक) + अप्रयुक्त ब्याज, शुल्क, लागत एवं व्यय आदि	रू 21 लाख रू 2.10 लाख रू 0.10 लाख	श्री अमित चावला मो0 9140740461 इमेल varana@uco.bank.in

नियम व शर्ते - 1. विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स 2002' में बताई गई नियम व शर्तों के अधीन होगी। विक्रय की विस्तृत नियम व शर्ते https://baanknet.com और https://www.uco.bank.in के वेबसाइट/ वेबपोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। 2. सम्पत्ति को '' जैसा है, जहाँ है'' और ''जैसा है, वैसा है '' के आधार पर बेचा जा रहा है। 3. ऊपर ''सम्पत्ति का विवरण'' में बताई गई सुरक्षित सम्पत्तियों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर दी गई हैं, लेकिन इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नही होगें। 4. विक्रय अभोहस्ताक्षरी द्वारा https://baanknet.com URL वाली वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी और यह 18.07.2026 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी। 5. बैंक नीलामी में भाग लेने के लिए खुद की बोली (self-bid) लगाने हेतु किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वे किसी भी बोली को स्वीकार करें या समस्त बोलीयों को अस्वीकार कर दें (यदि स्वीकार्य न हों), नीलामी की शर्तों में बदलाव करें, या बिना कोई कारण बताये और बिना किसी खर्च या मुआवजें के नीलामी को कभी भी स्थगित / रद्द/ टाल/बंद कर दें, इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

नोटः यदि प्रकाषित विज्ञापन में कोई त्रुटि हो जाती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाषित विज्ञापन को रही माना जाये।

दिनांकः 10.06.2026, स्थानः वाराणसी

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक